

पहुँची थी उनको सरकार ने अनुसूचित वित्तीय सहायता के रूप में अब तक 1,83,615 00 रुपये मन्ज़ूर किये हैं ।

Wage Board for Sugar Industry

2344. Shri Esvara Reddy: Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether the Second Wage Board for Sugar Industry has submitted its report recommending interim relief;

(b) if not, how much time it will take to submit the interim report; and

(c) when the Wage Board is likely to submit its final report to Government?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Yes, the Board has made two interim recommendations. Copies of Government Resolutions on the subject laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-836/67]

(b) Does not arise.

(c) It is not possible to indicate precisely when the Board would be able to submit its final recommendations.

Wage Board for Chemicals and Fertilizer Industries

2345. Shri K. Anirudhan:

Shri Umanath:

Shri K. M. Abraham:

Shri P. P. Esthose:

Shri Viswanatha Menon:

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:

(a) the last date for submitting the reply to the questionnaire of the Wage Board for Heavy Chemicals and Fertilizer Industries;

(b) whether the INTUC has submitted its reply, and if so, when; and

(c) if the answer to part (b) is in

the negative, whether it has adversely affected the work of the Wage Board?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) The original time limit of 1st November, 1966 was extended to 31st December, 1966, but the replies received after this date were also accepted.

(b) The reply of the Indian National Chemical Workers' Federation, which is affiliated to the INTUC, was received on 22nd April, 1967.

(c) Does not arise.

कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति

2346. श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री धनबाद की कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति के बारे में 5 अप्रैल, 1967 के अन्तर्गत प्रश्न संख्या 525 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दमबंद अधिवेशन के निष्कर्षों पर इस बीच आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है, और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कितना समय और लगेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) जैसे कि 5 अप्रैल, 1967 के प्रश्न संख्या 525 के उत्तर में यह कहा गया है कोयला खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के 10वें अधिवेशन के निर्णय सभी सम्बन्धित पक्षों के आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिए गए हैं। अधिकांश निर्णयों पर नियोजकों द्वारा कार्यवाही करना अपेक्षित है और शीघ्र कार्यवाही कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। जो निर्णय सरकार से संबंधित हैं उन पर भी शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।